किसान कल्याण उत्थान हमारी प्राथमिकता- मु.मंत्री भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में किसानों को लाभान्वित किया जाएगा

जयपुर, 19 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस (30 मार्च, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वृहद् कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान एवं वंचित वर्ग को राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेगी।

उन्होंने कहा कि 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को सुशासन के जरिए धरातल पर उतार रही है। शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत प्रदेश के अन्नदाता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 28 से 30 मार्च के बीच किसान उत्पादक संगठनों के 3 दिवसीय मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

यह आयोजन एफपीओ के लिए बाजार सम्पर्क, ब्रांड निर्माण, बिक्री संवर्धन और क्षमता विकास को मजबूत बनाने तथा एफपीओ को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार भी प्रदान करेगा। साथ ही, किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांव-ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

- उन्होंने बताया कि 28 मार्च से 30 मार्च तक किसानों के लिए तीन दिवसीय मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा तथा किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाएगा।

राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण, निर्माण श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण, डेयरी बूथ आवंटन, विद्युत चलित चाक का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

संघ ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंबेडकर से सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या आज औरंगज़ेब प्रासंगिक हैं, तो उन्होंने नहीं प्रासंगिक नहीं है। ज्ञातव्य है कि औरंगज़ेब की कब्र हटाने की मुहिम संघ से सम्बंधित संगठनों विश्व हिंदु परिषद व बजरंग दल ने छेड़ रखी है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी विहिप बजरंग दल द्वारा औरंगज़ेब का मुद्दा उठाने पर सवाल उठाया और कहा कि यह तो 300 साल पहले मर चुका है अम्बेडकर ने प्रतिनिधि सभा की मीटिंग के एजेंडा की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधि सभा आर.एस.एस. की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। अम्बेडकर ने कहा संघ की 32 इकाइयों के प्रमुख इसमें भाग लेंगे। भाजपा की तरफ से जे.पी. नड्डा भाग लेंगे।

उन्होंने कहा प्रतिनिधिसभा में दो प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। पहला बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है तथा दूसरा प्रस्ताव संघ जिसकी स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी के 100 साल के सफर से सम्बंधित है।

इस वर्ष विजयदशमी को आर.एस.एस. के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अम्बेडकर ने बताया हर साल 12000 युवा संघ में शामिल होते हैं। संघ के युवा सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिनिधि सभा में संघ अपने मुख्य लक्ष्य, हर गांव में शाखा खोले जाने, की भी समीक्षा करेगा।

पंजाब पुलिस ने डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया

पंजाब पुलिस ने 13 माह से बंद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया है

चंडीगढ़, 19 मार्च। पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा-पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड तोड़ दिए गए।

पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद कल हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर पर पहुंचेगी, जिसके बाद सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाई जाएगी और फिर शंभू बॉर्डर से जीटी रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।

इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बुधवार को 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी शामिल हुए। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 4 मई को होगी। इसमें पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली या कहीं और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। किसान 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। तब दिल्ली जाते वक्त हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें वहां रोक लिया था।

- इधर बुधवार को किसानों व केन्द्र सरकार के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही।

'एक दिन में 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समिति बनेगी।

कोचिंग सेन्टर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और विद्यार्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक संबल प्रदान करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी।

कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन नहीं देगा और न ही किसी तरह के अन्य विज्ञापनों में भाग लेगा।

कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पूरी फीस जमा कर देता है और अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो शेष अवधि के लिए पूर्व में जमा फीस दस दिन में वापस देनी होगी।

हर कोचिंग सेंटर को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल विकास के लिए काउंसिल सेशन करने होंगे।

कोचिंग संस्थान किसी भी विद्यार्थी को एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढाएंगे। प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद, प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

थप्पड कांड के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कई मामले दर्ज कराए गए हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जनप्रतिनिधि का चुनाव लड रहे याचिकाकर्ता ने चुनावी ड्यूटी कर रहे सरकारी अधिकारी से मारपीट की है। यदि जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो इससे आमजन में क्या संदेश जाएगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर रखा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वहां ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठा था। इस दौरान मीणा ने अधिकारियों पर ग्रामीणों से जबरन मतदान कराने का आरोप लगाए। इसके बाद नरेश मीणा ने मतदान बूथ पर मौजूद एसडीएम अमित चौधरी से धक्का-मुक्की की और थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ अलग-अलग कई मामले दर्ज किए थे।

एक तरफ भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलाये जाने के लिये, बाँग्लादेश उन्हें वापस भेजने का अनुरोध कई बार कर चुका है। भारत को बाँग्लादेशियों के भारत आने पर इसलिये सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि भारत, बाँग्लादेश को रेल, न्यूक्लियर पावर प्लान्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों तथा रक्षा-खरीद के लिये 7 बिलियन डॉलर दे चुका था, और इनमें से कुछ प्रोजेक्टों के अवरुद्ध होने की संभावना थी। इस माह के शुरु में, भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाँग्लादेश में भारत के कुछ प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं तथा दोनों पक्षों ने "प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो" की व्यवस्थाओं पर चर्चा की थी। हसीना की सरकार के हटने के बाद से भारत व बाँग्लादेश के रिश्तों में भारी तनाव व्याप्त है।

'ईडी पिछले दस साल में केवल दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोयला घोटाले के सिलसिले में, तृणमूल महासचिव अभिषेग बनर्जी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले के प्रकरण में एक अन्य केन्द्रीय एजेंसी, सीबीआई द्वारा पेश की गई चार्जशीट में भी है। इस केस में वे इस समय ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

माकपा सांसद एए रहीम ने अपने गैर-तारांकित प्रश्न में वित्त मंत्रालय से पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में सांसदों, विधायकों तथा स्थानीय निकायों के नेताओं के खिलाफ कितने केस दर्ज हुये। इन केसों का राज्य एवं पार्टी-वार ब्रेकअप बताया जाये तथा यह भी बताया जाये कि इनमें से कितने नेता दोषी पाये गये तथा कितने निर्दोष घोषित किये गये।

उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या पिछले 10 वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केसों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि एजेंसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज केसों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।

राष्ट्रीय विपक्षी दल प्राय: ईडी तथा सीबीआई जैसी केन्द्रीय एजेन्सियों को भाजपा की "वॉशिंग मशीन" कहते रहे हैं। माकपा सांसद द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न- क्या सरकार ने इस एजेन्सी की दक्षता बढ़ाने के लिये कोई कदम उठायें हैं- के उत्तर में मंत्री ने लिखा: "भारत सरकार की लॉ-एन्फोर्समैंट एजेन्सी, ईडी को प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचैंज मैनेजमैंट एक्ट 1999 तथा फ्यूज़िटिव इकोनॉमिक ऑफेन्डर्स एक्ट 2018 के प्रवर्तन (एन्फोर्समैंट) की जिम्मेदारी सौंपी है। ईडी विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर इनसे संबंधित मामलों की जाँच-पड़ताल करती है तथा राजनैतिक सम्बद्धता, धर्म तथा अन्य आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करती है। ईडी की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के लिये खुली रहती है। एजेंसी विभिन्न न्यायिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेह है।" इन न्यायिक संस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसने पिछले नवम्बर में चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि एजेंसी द्वारा दर्ज केसों में दोष-सिद्धि की दर बहुत कम है। अदालत ने एजेंसी से कहा था कि वह अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पर ध्यान दे। शीर्ष अदालत ने पूछा था कि किसी व्यक्ति को ट्रायल के तहत कितने समय तक रखा जा सकता है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में गिरफ्तारी के मामले में समान नीति अपनाये जाने की जरूरत बताई थी।

18 पत्रकारों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंजूर की गई है उनमें से दो पत्रकार दिवंगत हो चुके हैं उनकी सम्मान निधि प्रतिमाह उनकी पत्नियों को (आधी राशि) नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

वन रक्षक भर्ती परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वी.के. सिंह ने बताया कि पेपर लीक से संबंधित एफआईआर बांसवाड़ा में दर्ज हुई थी। गुरूवार को चारों आरोपियों को बांसवाड़ा कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, 13 नवम्बर 2021 को आयोजित हुई थी। इस दौरान सांवला राम जाट के घर पर उसकी महिला मित्र शारदा पुत्री नगाजी भील सहित छह लोगों को पेपर पढ़ाया गया था। एसओजी ने बुधवार को सांवला राम जाट के घर पर पेपर पढ़ने और तबीयत खराब होने पर पेपर देने के बाद भी फेल होने वाली शारदा भील को गिरफ्तार किया। वहीं भीयाराम (31) निवासी अरटवाव पुलिस थाना गुढामलानी जिला बाड़मेर हाल पुलिस कांस्टेबल पुलिस थाना डबोक उदयपुर को गिरफ्तार किया। एसओजी ने कांस्टेबल देवाराम (34) निवासी मीरपुरा पुलिस थाना करडा जिला जालौर हाल पुलिस कांस्टेबल रिजर्व पुलिस लाइन, उदयपुर को गिरफ्तार किया। देवाराम ने अपनी दो महिला मित्र रेशमी चिलका और शारदा को पेपर सांवला राम जाट के घर पर पढ़ाया। वहीं कांस्टेबल कमलेश कुमार (30) निवासी मीरपुरा पुलिस थाना करडा जिला जालौर हाल पुलिस कांस्टेबल रिजर्व पुलिस लाइन, उदयपुर ने अपने एक साथी को सांवला राम के घर पर वन रक्षक का पेपर पढ़ाया और परीक्षा सेंटर तक छोड़ने गया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908